दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-६९ वा | शनिवार १३ दिसंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर टिकीं महाराष्ट्र की नजरें!

अध्यक्ष-सभापती लेंगे फैसला या टालते रहेंगे?

शीतकालीन अधिवेशन डायरी

- जमीर काझी

नागपुर : ७२ हजार करोड़ रुपये की पुरवणी मांगों को मंजूरी देने के लिए बुलाए गए सिर्फ ७ दिन के हिवाळी अधिवेशन का अब अंतिम सप्ताह शुरू हो रहा है। सरकार आखिरी दो दिन में निधि मांगें और लंबित विधेयक पास कराने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद सभापती राम शिंदे इस सत्र में विपक्ष के नेता की नियुक्ति का फैसला करेंगे या फिर सुविधा के अनुसार टालते रहेंगे? इस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं।

आज ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दोनों पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात कर इसी सत्र में नियुक्ति करने की जोरदार मांग की, लेकिन जानकारों के अनुसार इसकी संभावना बेहद कम है।

पड़लकर-आव्हाड मारपीट प्रकरण का रिपोर्ट पेश पावसाळी सत्र के दौरान विधानमंडल लॉबी में भाजपा के विवादास्पद विधायक गोपीचंद पड़लकर और शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच हुई खुली हाथापाई की जांच रिपोर्ट इस सत्र में पेश कर दी गई है। विशेषाधिकार समिति ने पड़लकर समर्थक ऋषिकेश टकले और आव्हाड समर्थक नितीन देशमुख को दो दिन की साधारण सजा तथा २०२९ तक विधान भवन में प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश की है। साथ ही इस सत्र में १५ विधायकों द्वारा अपने समर्थकों को विधानमंडल में प्रवेश पास दिलकर नियम तोड़ने की बात सामने आई है। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

राज्य के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों में विपक्ष के नेता का पद खाली

महाराष्ट्र विधानमंडल के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) में विपक्ष के नेता का पद रिक्त है। सत्ताधारी कभी कहते हैं कि विपक्ष के पास जरूरी १०% सदस्य नहीं हैं, तो कभी कहते हैं कि यह फैसला पूरी तरह अध्यक्ष-सभापती का है। लेकिन महाविकास आघाड़ी नेताओं का दावा है कि जब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तब तक कोई नियुक्ति नहीं होगी - यह सबको पता है।

आदित्य ठाकरे को बनाने की अफवाह का खंडन

सत्ताधारी खेमे में यह जोर-शोर से अफवाह फैलाई गई थी कि उद्धव ठाकरे भास्कर जाधव के बजाय अपने बेटे आदित्य ठाकरे को विपक्ष का नेता बनवाना चाहते हैं। ठाकरे पिता-पुत्र ने इस फेक नेरेटिव का खुलकर खंडन किया। फिर भी उद्धव ठाकरे ने आज अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलकर भास्कर जाधव की नियुक्ति के लिए स्मरण-पत्र दिया और सत्र खत्म होने से पहले दोनों सदनों में विपक्ष के नेता घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता को सदन में अपनी बात रखने का हक और मान-सम्मान होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भाजपा के सिर्फ तीन विधायक थे, फिर भी केजरीवाल ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया था। महाराष्ट्र में यह क्यों नहीं हो रहा?

उद्धव ठाकरे ने साथ ही उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह किसी कानून में कहीं नहीं है, इसलिए इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।

अब देखना यह है कि सत्र के अंतिम दो दिन में अध्यक्ष और सभापती इस संवैधानिक पद पर फैसला करते हैं या फिर इसे भी अगले सत्र तक टाल देते हैं। पूरे विपक्ष की नजर इसी पर लगी हुई है।

गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर श्रद्धांजलि, जाति जनगणना को मंजूरी-उनकी संसद में उठाई मांग पूरी हुई

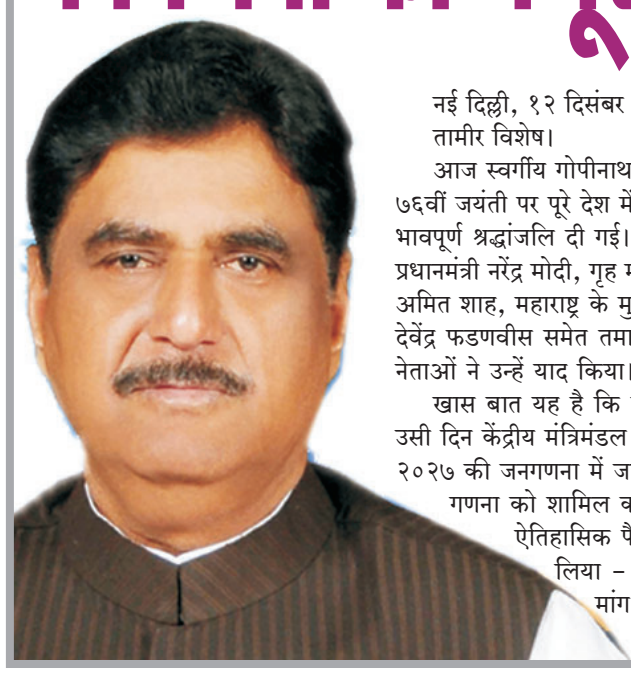

नई दिल्ली, १२ दिसंबर २०२५ तामीर विशेष।

आज स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की ७६वीं जयंती पर पूरे देश में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम नेताओं ने उन्हें याद किया।

खास बात यह है कि ठीक उसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २०२७ की जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया - यह वही मांग थी जिसे गोपीनाथ मुंडे ने अपने जीवनकाल में संसद के दोनों सदनों में बार-बार जोर-शोर से उठाया था।

मुंडे की संसद में पुरानी आवाज़ अब हुई पूरी

वर्ष २०१० में लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे ने स्पष्ट कहा था, जब तक जाति आधारित सही आंकड़े नहीं आएंगे, सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। जनगणना में जइउ की गिनती अनिवार्य की जाए।

उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया था, लेकिन उनकी मांग उस समय पूरी नहीं हो सकी।

आज कैबिनेट के फैसले के बाद भाजपा नेताओं ने इसे गोपीनाथ मुंडे के सपने की पूर्ति बताया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,

आज गोपीनाथराव मुंडे जी की जयंती पर उनकी सबसे बड़ी संसदीय मांग पूरी हुई। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। १९३१ के बाद पहली बार पूर्ण जाति जनगणना होगी।

जनगणना के प्रमुख बिंदु (फिर से संक्षेप में):

बजट: ११,७१८ करोड़ रुपये

पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना

जाति गणना शामिल (डउ/डढ के साथ-साथ जइउ की सभी उप-जातियां)

समय: अप्रैल २०२६ से शुरू, रेफरेंस डेट १ मार्च २०२७

३.४ लाख कर्मचारी तैनात

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया:

आज लोकनेते के सपने का दिन है। जिस जाति जनगणना के लिए उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई थी, उसी को मोदी सरकार ने मंजूरी दी। गोपीनाथ मुंडे अमर रहें!

गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने भी भावुक संदेश में लिखा, पापा आज बहुत खुश होंगे। उनकी लड़ाई आज पूरी हुई।

इस तरह १२ दिसंबर २०२५ का दिन गोपीनाथ मुंडे की स्मृति में हमेशा याद रखा जाएगा - जिस दिन उनकी संसद में उठाई सबसे बड़ी मांग आखिरकार पूरी हो गई।

महाराष्ट्रने खोया एक सभ्य और सुसंस्कृत शीर्ष नेतृत्व-देवेंद्र फडणवीस

नागपुर, १२ दिसंबर: जमीर काजी

महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र में शालीनता और सुसंस्कृतता की परंपरा को बनाए रखने वाले तथा उसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने वाले नेतृत्व के रूप में वरिष्ठ नेता शिवराज पाटील चाकूरकर सदा स्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर को इसी भावपूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की है।

उन्होंने कहा कि उनके निधन से राजनीति और समाजकारण में एक ऊँचे मार्गदर्शक नेतृत्व को हमने खो दिया है। शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, चाकूरकर जी ने लातूर के नगराध्यक्ष के रूप में राजनीति में कदम रखा। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, संसद की अनेक समितियों के सदस्य, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा पंजाब के राज्यपाल तक का उनका शानदार सफर रहा। वे सात बार लोकसभा सदस्य चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संसदीय प्रक्रिया से जुड़े कई नवाचारी उपक्रमों को प्रोत्साहन दिया। वकील होने के नाते संविधान का गहरा अध्ययन रखने वाले चाकूरकर जी ने लोकसभा की संसदीय कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाया। सिद्धांतनिष्ठ, अभ्यासपूर्ण और दृढ़ता से अपनी बात रखने वाले नेता के रूप में देश की राजनीति में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उनके निधन से राजनीति-सामाजकारण में सभ्यता-सुसंस्कृतता को बनाए रखने वाला, लोकतंत्र में गहरी आस्था रखने वाला एक ज्येष्ठ नेतृत्व और महाराष्ट्र का सुपुत्र हमने खो दिया है। यह इस क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चाकूरकर परिवार और उनके कार्यकर्ताओं पर गहरा आघात हुआ है।

सुसंस्कृत और अभ्यासू व्यक्तित्व को खोया: अजित पवार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर के निधन से देश की राजनीति ने एक सभ्य, सुसंस्कृत और अभ्यासू व्यक्तित्व खो दिया है, ऐसी शोक-संवेदना उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने व्यक्त की है।

अजित पवार ने अपने शोक संदेश में कहा, शिवराज पाटील चाकूरकर जी ने लोकसेवा का एक नया आदर्श स्थापित किया था। सादगी और नैतिक मूल्यों के वे जीवंत प्रतीक थे। अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंजाब के राज्यपाल जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी उन्होंने राजनीति में नैतिकता को हमेशा जीवित रखा। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लोकसभा का आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, संसद के कार्य की लाइव टेलीकास्ट सुविधा, नई लाइब्रेरी बिल्डिंग जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्हें गति प्रदान की।

बीड़ के मांजरसुंबा घाट में डीज़ल टैंकर का भीषण विस्फोट; आग ने फैलाया कहर

तामीर संवाददाता

बीड़: मांजरसुंबा घाट (जि. बीड़) में शुक्रवार दोपहर डीज़ल टैंकर के पलटने से जबरदस्त विस्फोट हुआ। सोलापुर-धुले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस अपघात के बाद टैंकर से डीज़ल दूर-दूर तक सड़क पर फैल गया, जिसके कारण लगभग एक किलोमीटर तक आग झाड़ियों और सड़क किनारे फैलती चली गई। तेज़ लपटें और धुएँ के बड़े बादल कई किलोमीटर दूर से दिस रहे थे, जिससे क्षेत्र में दहशत पैदा हो गई

हादसे के बाद उभरे सवाल।

क्या सरकारी तंत्र और डीज़ल परिवहन कंपनियाँ जागेंगी?

किसकी लापरवाही ने जन्म दिया इस आग के महासंकट को?

घटना का संक्षेप:

टैंकर पलटा और हुआ भीषण धमाका

राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते समय अचानक डीज़ल ले जा रहा टैंकर पलट गया। पलटते ही उसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ। देखते ही देखते सड़क पर बहे डीज़ल ने आग का रूप लिया और १००-२०० मीटर नहीं, बल्कि लगभग एक किलोमीटर तक झाड़ियों और सड़क किनारे आग फैल गई। पूरी घाटी चीख-पुकार और डर के माहौल में घिर गई।

टैंकर पूरी तरह जलकर खाक

धधकती आग ने टैंकर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि -

दुर्घटना किस कारण हुई?

टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर कहाँ हैं?

कोई व्यक्ति आग में फँसा तो नहीं?

स्थानीय लोग और यात्रियों में भय

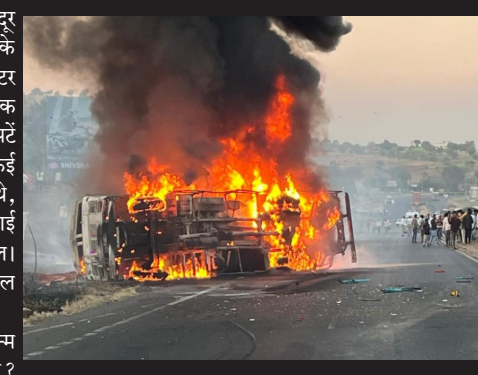

का वातावरण निर्माण हूवा था ।

फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर आइ मगर कुछ देर से

अग्निशमन दल की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और आग बुझाने का काम युद्धस्तरावर शुरू है सुरक्षा के लिए राजमार्ग के दोनों ओर की वाहतूक पूरी तरह बंद कर दी गई थी ।

अब उठते हैं गंभीर सवाल -

सरकार और डीज़ल कंपनियाँ कब जवाब देंगी?

१) क्या टैंकरों की नियमित सुरक्षा जांच होती है?

डीज़ल जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन करते समय क्या कंपनियाँ टैंकरों की फिटनेस, टायर, ब्रेक और वॉल्व की प्रतिदिन जांच करती हैं?

अगर करती हैं, तो फिर ऐसे हादसे बार-बार क्यों होते हैं?

२) क्या ड्राइवरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है?

अक्सर सामने आता है कि खतरनाक पदार्थ ढोने वाले वाहन अनुभवहीन या अधिक काम से थके हुए चालकों द्वारा चलाए जाते हैं।

क्या इस दुर्घटना में भी ऐसा ही हुआ?

३) राजमार्ग सुरक्षा प्रणाली कहाँ गायब थी?

इतने बड़े और संवेदनशील घाट क्षेत्रों में -

स्पीड कंट्रोल,

मोड़ पर चेतावनी संकेत,

इमरजेंसी लेन्स,

और सीसीटीवी निगरानी -

इन सबका प्रबंध क्यों नहीं है?

४) कंपनी और सरकार जिम्मेदारी लेगी या फिर जांच की फाइलें धूल खाएँगी? जनता का सवाल: एक टैंकर विस्फोट से अगर पूरा घाट जल सकता है, तो क्या हमारी सुरक्षा इतनी कमजोर है?

यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं - बल्कि एक चेतावनी है।

सरकार और डीज़ल कंपनियों को यह बताना होगा कि ऐसी खतरनाक घटनाएँ दोबारा न हों, इसके लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे?

सोयाबीन खरीद केंद्र के लिए मंत्री के ओएसडी द्वारा तीन लाख की मांग; बीड के व्यक्ति द्वारा वसूली?

विजय वडेट्टीवार का सनसनीखेज आरोप

रिपोर्टर: जमीर काज़ी

नागपुर - नांदेड़ और यवतमाल जिलों के किसानों की सोयाबीन फसल को खारिज किया जा रहा है। सोयाबीन खरीद केंद्र शुरू करने के लिए मंत्री के ओएसडी अभिजीत पाटिल और गर्जे तीन लाख रुपये की मांग कर रहे हैं, जबकि बीड के एक निजी व्यक्ति अखिल द्वारा यह रकम वसूले जाने का सनसनीखेज आरोप कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को लगाया।

विधानसभा में पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने किसानों की खारिज की गई सोयाबीन सीधे सदन में लेकर आए। अध्यक्ष और मंत्री के समक्ष उन्होंने पीड़ित किसानों की व्यथा रखी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाली सोयाबीन भी खरीद केंद्र पर खारिज की जा रही है, तो किसान जिएं या मरें?

वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाता है, लेकिन सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। विदर्भ में अधिवेशन चल रहा है, ऐसे समय किसानों को न्याय मिलना चाहिए, यह मांग उन्होंने की।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया। खरीद केंद्र शुरू करने के लिए कथित रूप से धन वसूली के आरोपों की जांच के निर्देश दिए और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

वडेट्टीवार ने नांदेड़ जिले के किसानों - गजानन तन्मने, संजय सिदखेड़े, भगवती किंदट, उल्हास किंदट, गजानन किंदट - की लिखित शिकायतें और वसूली करने वाले 'अकिल' नामक व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी सदन में प्रस्तुत किया।

पुलिस की वर्दी पर 'बॉडी कैमरा' लगा होगा तभी कटेगा चालान

अब बिना बॉडी कैमरा के ट्रैफिक पुलिस नहीं वसूल सकेगी जुर्माना

बीड :

महाराष्ट्र के वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब राज्य में ट्रैफिक पुलिस केवल तभी चालान काट सकेगी और जुर्माना वसूल सकेगी, जब उसकी वर्दी पर बॉडी कैमरा लगा होगा और वह चालू हालत में होगा।

यह महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। उन्होंने बताया कि गोवा में यह प्रयोग बहुत सफल रहा है, उसी तर्ज पर अब पूरे महाराष्ट्र में इसे लागू किया जाएगा।

इस नए नियम के मुख्य बिंदु:

बॉडी कैमरा अनिवार्य: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी पर बॉडी कैमरा नहीं होगा तो वह किसी भी वाहन चालक से जुर्माना नहीं ले सकेगा।

पूरा घटनाक्रम होगा रिकॉर्ड: चालान काटते समय की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इससे पारदर्शकता आएगी और बेवजह परेशान करने या रिश्वत की शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी।

फास्ट टैग से भी कटेगा चालान: अब सिर्फ नकद ही नहीं, फास्ट टैग के जरिए सीधे बैंक खाते से भी जुर्माना कट सकेगा। इससे डिजिटल प्रक्रिया तेज होगी और नकदी का लेन-देन खत्म होगा।

भ्रष्टाचार पर लगाम: वीडियो सबूत रहने से न तो पुलिस मनमाने ढंग से चालान कर सकेगी और न ही कोई नागरिक गलत आरोप लगा सकेगा।

श्री फडणवीस ने कहा कि यह व्यवस्था जल्द ही पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इससे एक तरफ वास्तविक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी और अड़ंगेबाजी से मुक्ति मिलेगी।

नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि लंबे समय से इस तरह के पारदर्शी सिस्टम की जरूरत थी।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

गोपीनाथगड की स्थापना वंचितों-उपेक्षितों के लिए ही हुई; उसी आदर्श पर चल रही हूं - मंत्री पंकजाताई मुंडे

लोकनेता की जयंती पर गोपीनाथगड पर उमड़ी भारी भीड़, राज्यभर से हजारों कार्यकर्ता समाधि पर नतमस्तक

परली वैजनाथ । १२ दिसंबर

गोपीनाथगड की स्थापना मूलतः इसलिए हुई है ताकि लोकनेता गोपीनाथ मुंडे साहब से प्यार करने वाला हर शख्स यहां आकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर सके और अपने सुख-दु:ख उनके चरणों में रख सके। धरती पर यह एकमात्र ऐसा किला है जिसे एक बेटी ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया है। वास्तव में यह गढ़ मैंने नहीं, भगवान ने बनवाया है। मुंडे साहब ने जीवन का हर पल वंचितों और पीड़ितों के लिए समर्पित किया था। उसी आदर्श पर मैं अपनी यात्रा चला रही हूं।

ये भावुक शब्द हैं महाराष्ट्र की पर्यावरण एवं पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे के, जो उन्होंने लोकनेता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर गोपीनाथगड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

सुबह सबसे पहले पंकजाताई मुंडे, मात्री, मातोश्री प्रज्ञाताई मुंडे, पूर्व सांसद डॉ. प्रीतमताई मुंडे, मंत्री धनंजय मुंडे तथा पूरे मुंडे परिवार ने समाधि स्थल पर मत्था टेका। इसके बाद पंकजाताई ने कहा, मुंडे साहब का पूरा जीवन वंचितों के लिए था। वे हमेशा खुद से पहले दूसरों का सोचते थे। एक बार उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर ने सड़क पार कर रहे एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी अचानक मोड़ी। बच्चा तो बच गया, लेकिन मुंडे साहब को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में जब उन्हें होश आया तो सबसे पहला सवाल उन्होंने यही पूछा – 'वो बच्चा ठीक है न?

उसे कुछ हुआ तो नहीं?' यह था मेरा पिता – जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी दूसरों की चिंता करते थे। मैंने आज समाधि के चरणों में यही प्रार्थना की है कि हममें उनकी बनाई संस्थाओं को और बड़ा करने की ताकत हो या न हो, लेकिन उन्हें मजबूत बनाए रखने और उनकी परंपरा को जीवित रखने का आशीर्वाद जरूर दें।

काम और अधिकारों का विकेंद्रीकरण

पंकजाताई ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि हर जनसेवा के काम का और अधिकारों का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उसी भावना से मैं भी काम और अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर रही हूं। पिछले साल से मैंने अपील की थी कि गोपीनाथगड पर भव्य आयोजन करने की बजाय हर कार्यकर्ता अपने-अपने इलाके में मुंडे साहब को प्रिय सामाजिक कार्य करके जयंती मनाए। इस बार भी राज्यभर के कोने-कोने में – ऊस के खेतों में, अस्पतालों में, अनाथालयों में, गरीबों को मदद पहुंचाकर – हजारों कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सेवा के जरिए जयंती मनाई। इससे मुंडे साहब को प्रिय सामाजिक न्याय की भावना सचमुच जीवित हो रही है।

गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान की ओर से जरूरतमंदों को कम्बल वितरण

जयंती के अवसर पर गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान की ओर से वैद्यनाथ मंदिर परिसर में सैकड़ों गरीब व जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कम्बल वितरित किए गए। इस दौरान प्रितेश तोतला, नितीन समशेट्टी, आश्विन मोगरकर, अनीश अग्रवाल, मौली आघाव सहित प्रतिष्ठान के पदाधिकारी मौजूद रहे।

इसके अलावा राज्यभर में रक्तदान शिविर, अन्नदान, जरूरतमंदों को आर्थिक-सामग्री सहायता जैसे सैकड़ों सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोपीनाथगड पर पूरे दिन श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही।

इंडिगो की एकाधिकार नीति से यात्रियों को भारी परेशानी, विमानन मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगें: वर्षा गायकवाड़

रनवे फनल जोन में रहने वाले हजारों परिवारों को बेदखली का दबाव, बिजली-पानी-रास्ते बंद कर प्रशासन की धौंस

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के लिए हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का जो सपना दिखाया था, वह महज दिवास्वप्न साबित हुआ है। आज हवाई यात्रा आम लोगों के लिए लूट-खसोट और शोषण का माध्यम बन चुकी है। पिछले छह-सात दिनों में इंडिगो एयरलाइंस ने जो अव्यवस्था फैलाई, उससे हजारों यात्रियों को भयानक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान किसी ने भी यात्रियों से बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। इस गड़बड़ी से देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई। यह सब एक ही एयरलाइन के एकाधिकार (मोनोपॉली) की वजह से हुआ है। सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्री को इस घटना पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह मांग मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ ने की है।

संसद में बोलते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि पहले देश में किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, एयर डेक्कन, जेटलाइट, सहारा, एयर एशिया इंडिया जैसी करीब २० एयरलाइंस सेवाएं दे रही थीं, लेकिन सरकार की ठोस नीति न होने से एक-एक करके सभी बंद होती गईं। अब सिर्फ एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो जैसी कुछ कंपनियां बची हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा इंडिगो का है। इसी एकाधिकार के कारण यह सारी अव्यवस्था हुई। एकाधिकार होने की वजह से उपभोक्ताओं का खुलेआम शोषण हो रहा है। ५-६ हजार रुपये का टिकट २०-३० हजार तक पहुँच गया। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को पीने का पानी तक नहीं मिला, कोई उनसे बात करने नहीं आया। अब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो को अनुमति दे दी गई है, लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इस तरह की अव्यवस्था रोकने का कोई प्लान है भी या नहीं?

वर्षा गायकवाड़ ने आगे कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पर णउऊ्र –डऊ्र और फ्यूल सरचार्ज के नाम पर यात्रियों से भारी लूट हो रही है। एक पानी की बोतल या समोसा भी लेना हो तो कीमत आसमान छूती है। पार्किंग चार्ज एक घंटे के ३७० रुपये, दो घंटे के ४०० रुपये और छह घंटे के १००० रुपये तक वसूले जाते हैं। एयरपोर्ट के दुकानदारों से अदाणी कंपनी भारी किराया वसूलती है और बिक्री का बड़ा हिस्सा भी लेती है, यानी दोहरी लूट। जगह-जगह दुकानें लगा दी गई हैं, यात्रियों के चलने तक की जगह नहीं बची। अदाणी के नुकसान की भरपाई के लिए अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से णउऊ्र १७५ रुपये बढ़ाकर ३८५६ रुपये करने का प्रस्ताव है, जिसे रोकने की कोई कोशिश सरकार नहीं कर रही। सवाल यह है कि सरकार अदाणी की मनमानी क्यों बर्दाश्त कर रही है? यह मुंबई की हवाई यात्रा को महंगा बनाने और पर्यटन को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। इस लूट को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर अदाणी एंड संस रख देना चाहिए।

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुंबई एयरपोर्ट के रनवे फनल जोन में पिछले ७० सालों से १८ लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक हैं। फनल जोन होने की वजह से पुरानी इमारतों का पुनर्विकास नहीं हो पाता। अब इस इलाके को एक उद्योगपति को सौंपने की तैयारी है और वहाँ के निवासियों को जबरन बेदखल किया जा रहा है। उनकी बिजली-पानी काट दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस इलाके में एयरलाइंस कर्मचारियों की कॉलोनियाँ और सफाई कर्मचारी भी रहते हैं। सरकार अदाणी को जमीनें देती है, सारे नियम उसके पक्ष में बनाती है, लेकिन इन आम नागरिकों के लिए कोई नीति क्यों नहीं बनाती? केंद्र और राज्य सरकार को इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। मैं लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रही हूँ, मंत्रियों से मिल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। सरकार को इस मामले में तुरंत ध्यान देकर इसे हमेशा के लिए हल करना चाहिए।

पांगरी रोड सहित बीड शहर में आवारा कुत्तों का खौफ, रात में निकलना हुआ मुश्किल

छोटे बच्चों व महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा, नागरिकों में दहशत

बीड (रिपोर्टर) :

बीड शहर के पांगरी रोड-चक्रधर नगर इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि रात के समय लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। कुत्तों के बड़े-बड़े झुंड सड़कों पर घूमते हैं और राहगीरों, खासकर मोटरसाइकिल सवारों व देर रात लौटने वाले लोगों पर अचानक हमला कर काट ले रहे हैं।

जालना रोड, बार्शी रोड, नगर रोड, पेठ बीड, मोमीनपुरा, स्वराज्यनगर समेत शहर के लगभग सभी मोहल्लों में यही हाल है, लेकिन पांगरी रोड और चक्रधर नगर में कुत्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक साथ १५-२० कुत्तों का झुंड सड़क पर बैठा रहता है। ये कुत्ते रात १० बजे के बाद जोर-जोर से भौंकते हैं और आने-जाने वालों के पीछे दौड़ पड़ते हैं।

पिछले कुछ दिनों में कई लोग कुत्तों के काटने के बाद एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंचे हैं। छोटे बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, मेरी ८ साल की बेटी शाम को ट्यूशन से लौट रही थी, तभी कुत्तों ने उसे घेर लिया। किसी तरह हमने उसे बचाया।

नागरिकों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। पांगरी रोड और चक्रधर नगर के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर चेतावनी दी है कि अगर नगरपालिका ने एक सप्ताह के अंदर बड़े पैमाने पर कुत्तों की नसबंदी और पकड़ अभियान नहीं चलाया, तो वे मुख्य मार्ग पर आंदोलन करेंगे।

लोगों की प्रमुख मांगें :

तुरंत खतरनाक कुत्तों को पकड़कर -इउ सेंटर भेजा जाए

पूरे शहर में बड़े स्तर पर नसबंदी कैंप लगाए जाएं

रात में गश्त करने वाली विशेष टीम बनाई जाए

नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि वे जल्द ही टेंडर निकालकर कुत्तों की नसबंदी शुरू करवाएंगे, लेकिन नागरिक बोले – अब और इंतजार नहीं होगा।

राज्य में शिक्षा व्यवस्था हुई छिन्न-भिन्न, जिला परिषद स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद रिक्त

विधानसभा में सदस्यों ने दिखाया आक्रोश

जमीर काझी

नागपुर :

महाराष्ट्र राज्य के जिला परिषद स्कूलों में कुल ३७ हजार शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। जिला परिषद स्कूलों में शिक्षा का पूरी तरह खेळखंडोबा (बुरा हाल) हो गया है। इसलिए सरकार इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरे, ऐसी मांग सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मिलकर विधानसभा में की। सरकार सदन में जो आंकड़े दे रही है, वे झूठे हैं, ऐसा आरोप भी लगने से सदन में कुछ देर हंगामा हुआ।

भाजपा के विधायक सुधीर मुनगंटीवार, कांग्रेस विधायक दल नेता विजय वडेट्टीवार, भास्कर जाधव, नाना पटोले आदि ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान मंत्री से राज्य की जिला परिषद प्राथमिक शिक्षकों की बदली और रिक्त पदों के बारे में सवाल उठाए।

इस दौरान विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, एक तरफ शिक्षक पद रिक्त हैं, दूसरी तरफ राज्य में ५५ हजार जिला परिषद स्कूल बंद करने की खबरें आ रही हैं। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद सरकार इसका ध्यान नहीं रख रही। चंद्रपुर जिले में भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सात क्लास और केवल तीन शिक्षक – बच्चे क्या पढ़ेंगे? उन्होंने मांग की कि सरकार पूरे राज्य में कितने शिक्षक पद रिक्त हैं, यह स्पष्ट बताए और एक निश्चित समय-सीमा में सभी पद भर दे।

जवाब में मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा कि राज्य में केवल १५ हजार शिक्षक पद रिक्त हैं। इस पर वडेट्टीवार ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा, राज्य में ३७ हजार पद रिक्त हैं। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार का पोर्टल 'पवित्र' नाम का है, लेकिन उसमें अपवित्र काम हो रहा है।

इस मुद्दे पर मंत्री गोरे ने स्वीकार किया कि चंद्रपुर जिले में ४७२ शिक्षक पद रिक्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए नई व्यवस्था लाने की जरूरत है।

बीड तालुके में व्यक्तिगत लाभ के मस्टर तुरंत शुरू किए जाएं – शिवसेना का जोरदार प्रदर्शन

पंचायत समिति कार्यालय के सामने शिवसैनिकों का तीव्र आंदोलन

बीड (रिपोर्टर) :

बीड तालुके में मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ के सभी मस्टर अचानक बंद कर दिए गए हैं। इन्हें फौरन शुरू करने और गरीब मजदूरों को काम देने की मांग को लेकर आज शिवसेना (णइढ) कार्यकर्ताओं ने तालुका पंचायत समिति कार्यालय के मुख्य द्वार पर तीव्र प्रदर्शन किया।

शिवसैनिकों की प्रमुख मांगें:

व्यक्तिगत लाभ योजना में एक व्यक्ति से सिर्फ २० मांगें ही लेने की सीमा तुरंत हटाई जाए, ताकि तालुके के सभी पात्र लाभार्थियों को काम मिल सके।

तालुके के कई गांवों में रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत वर्क-कोड बड़े पैमाने पर डिलीट कर दिए गए हैं। नए वर्क-कोड तत्काल मंजूर कर मस्टर शुरू किए जाएं।

तालुके में व्यक्तिगत लाभ के सभी बंद पड़े कामों के मस्टर फौरन चालू किए जाएं।

लंबित कुशल मजदूरी का भुगतान तुरंत किया जाए।

प्रदर्शन में सतीश शेळके, संतोष जाधव, आकाश जगताप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पंचायत समिति प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर तालुके में मस्टर शुरू नहीं हुए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

शिवसैनिकों ने कहा, तालुके के गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं, प्रशासन तुरंत काम शुरू करे, वरना हम सड़कों पर उतरेंगे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com